# पहले बूस्टर ने तो 'निहाल' कर दिया, अब दूसरे की तैयारी

**फ़रीदाबाद ( म.मो. )** घोषणा व उद्घाटन करके की शौकीन बल्कि केवल यही एक काम जानने वाले खट्टर ने करीब एक माह पूर्व इस शहर में ताबड़तोड़ शिलान्यास व उद्घाटन करते हुए सेक्टर 22 के निकट पुराने बने एक बूस्टर स्टेशन का उद्घाटन किया था। उस वक्त दावा किया गया था कि सेक्टर 22,23,24 व संजय कॉलोनी आदि में बसी लाखों की आबादी को अब पेयजल की कोई कमी नहीं रहेगी। इसके बावजूद जो पानी पहले 48 घंटे में एक बार दिख जाता था अब 72 घंटे बाद दिखता है।

बुधवार चार जनवरी को एफएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर राजपाल आईएएस ने दावा किया है कि वीरवार पांच जनवरी से डबुआ कॉलोनी, जवाहर कॉलोनी, उड़िया कॉलोनी, गाजीपुर आदि की कॉलोनियों में बसी करीब 70 हजार की आबादी को शुद्ध मीठा पेयजल मिलने लगेगा। इसके लिये उन्होंने सूर्य देवता भूमिगत टैंक से 20 लाख लीटर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति शुरू करा दी है। राजपाल ने बताया कि यह टैंक नगर निगम ने बना कर छोड़ दिया था जिसे बिजली कनेक्शन के आभाव में बंद कर दिया गया था। अब इसे करीब 26 करोड़ खर्च करके चालू कर दिया गया है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 2004-5 में इसका निर्माण किया गया था। वर्षों तक यूं ही पड़ा रहने के बाद सन् 2014-15 में इसे नगर निगम द्वारा चलाया गया था। लेकिन भारी कमीशनखोरी के आधार पर बनाया गया यह बूस्टर स्टेशन बहुत दिन तक न चल सका। दरअसल नगर निगम समेत तमाम भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों की यह नीति होती है कि निर्माण के नाम पर मोटा माल डकार कर उसे किसी न किसी बहाने की आड़ लेकर इस्तेमाल न किया जाय। इस बीच माल हजम करने वाले अफ़सर तो जा चुके होते हैं और वर्षों बाद आये नये अफसर कुछ धक्का पेल करके उसे चलाने के बाद बेकार घोषित कर देते हैं।

अब 2023 में सुधीर राजपाल ने इसकी कमान अपने हाथ में लेकर व भारी रकम खर्च करके इसे चालू करने की घोषणा कर दी है। लेकिन यह घोषणा भी धरातल पर खरी उतरती नजर नहीं आ रही। खबर लिखे जाने तक घोषित किये गये क्षेत्र में पानी सप्लाई की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। पहले की तरह ही तीन दिन बाद खारा पानी मिल पाता है। यह स्वास्थ्य के लिये निहायत ही खतरनाक होता है। जो लोग पीने का महंगा पानी नहीं खरीद सकते केवल वही लोग इसे पीने को मजबूर होकर भयानक बीमारियों के शिकार होते रहते हैं।

इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि 75 साल की आजादी के बाद मनाये जा रहे अमृतकाल महोत्सव तथा 6 साल से बनाये जा रहे स्मार्ट सिटी में आज मुख्यमंत्री व उनके सिपहसालार राजपाल पेयजल सप्लाई करने की खोखली घोषणायें करके जनता को बेवकूफ़ बनाने व सरकारी धन को लूटने में जुटे हैं।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार ज्यों ही वाटर सप्लाई शुरू की गई त्यों ही पाइप लाईन कई जगहें से फ़ट गई जिसके चलते बेशकीमती पानी सड़कों पर बहता रहा। कई दिनों तक इन पाईपों की मरम्मत होती रहेगी। उसके बाद कोई और पाईप लाईन कहीं से फटेगी अथवा कोई मोटर फुकेगी या कोई और क्लेश पैदा हो जायेगा क्योंकि मोटी कमीशनखोरी के चक्कर में न तो उत्तम क्वालिटी का सामान लगाया गया है और न ही कुशल कारीगर।

# पैदल चलने वालों के लिये फुटपाथ तो बने नहीं, सड़क पार करने को फुट ओवरब्रिज बनायेंगे

मेट्रो मोड़ पर सीवर का खड़ा पानी, इसी मोड़ पर फुटओवर ब्रिज बनाने की योजना

**फ़रीदाबाद ( म.मो. )** पूरे एनआईटी क्षेत्र में पैदल चलने वालों के लिये कहीं कोई फुटपाथ नहीं हैऔर जो कभी कहीं-कहीं था भी उस पर भी प्रशासन ने अवैध कब्जे करवा दिये हैं। साइकिल ट्रैक की तो बात ही न कीजिये। करीब तीन साल पहले बाटा मोड़ से कचहरी होते हुए बाइपास तक जाने वाली दो कि.मी. लम्बी सड़क के किनारे 18 लाख की लागत से साइकिल ट्रैक बनाया गया था। आज यह कहां है ढूंढने से भी नहीं मिलेगा।

काम के नाम पर लूटने-खाने में माहिर तथा जनता को बेवकूफ़ समझने वाले एफएमडीए अफसरों ने एनआईटी क्षेत्र में पांच फुट ओवरब्रिज, जिनके द्वारा लोग सड़क पार किया करेंगे, बनाने का निर्णय लिया है। इस तरह के फुटओवर ब्रिजों की आवश्यकता वहां होती है जहां तेज गति से इतने वाहन निकलते हों कि पैदल सड़क पार ही न की जा सके जैसे कि दिल्ली-मथुरा रोड।

एनआईटी की किसी भी सड़क पर कोई भी वाहन लगातार बिना रुके यानी जाम में फसे बिना एक कि.मी. भी नहीं चल सकता। जहां सदैव, हर सड़क पर वाहन जाम में ही फसे खड़े हों वहां भला सड़क पार करने के लिये कौन मूर्ख पुल पर चढेगा? लेकिन पुल बनाने वालों को इससे क्या लेना-देना। उन्हें तो पुलों के बनने से ही तो कमीशन के रूप में आय होगी। वे भी अच्छी तरह जानते हैं कि उनके बनाये पुलों पर चढ़ कर किसी ने सड़क पार नहीं करनी। इसलिये वे पुल भी ऐसे ही बनवायेंगे जो केवल दिखावे मात्र के हों और बनने के दो-चार साल बाद कबाड़ा बन कर बिखर जायें।

# जनता को ठगने व 'काम' पर लगाये रखने में खट्टर सरकार का कोई जवाब नहीं

**फ़रीदाबाद ( म.मो. )** राज्य की जनता से अधिक से अधिक वसूलने तथा उन्हें कम से कम देने के साथ-साथ उन्हें एक के बाद दूसरी लाइन में लगाये रखने में खट्टर की महारत का कोई जवाब नहीं। खट्टर ने ऐसा कोई महकमा नहीं छोड़ रखा जो जनता से हर तरह की वसूली बढ़-चढ़ कर न कर रहा हो। दूसरी ओर जनता को मिलने वाली तमाम सुविधाओं में कटौती दर कटौती की जा रही है। उन्हें लाइनों में लगाये रखने के लिये कभी आयुष्मान भारत कार्ड, कभी चिरायु कार्ड, कभी विकलांगता का नवीनीकरण, कभी आईडी बनवाने तो कभी उसे दुरुस्त करवाने के बाद अब परिवार पहचान पत्र को दुरुस्त कराने के लिये लोग सुबह से शाम तक लाइनों में लगे खड़े रहते हैं। इससे पहले इस कार्ड को बनवाने के लिये लाइनों में लगे रहे थे।

सरकार की सुविधायें प्राप्त करने के लिये परिवार पहचान पत्र को एक अनिवार्य शर्त के रूप में रखा गया है। सरकार से कुछ भी प्राप्त करने के लिये प्रार्थी के पास इस पहचान पत्र का होना अनिवार्य कर दिया गया है। आजकल इसका अधिकतम इस्तेमाल राशनकार्ड, आयुष्मान कार्ड, बुढापा एवं विधवा पेंशन तथा विकलांग पेंशन के लिये हो रहा है।

सरकार की तरफ़ से बदमाशी यह हो रही है कि किसी के भी परिवार पहचान पत्र में उसकी आय 1 लाख 80 हजार वार्षिक दिखाकर उसकी पेंशन काट दी जाती है। इसके अलावा परिवार में यदि किसी की सरकारी नौकरी हो अथवा किसी की भी आय 1 लाख 80 हजार से ऊपर हो तो बूढे या विधवा की पेंशन काट दी जायेगी। इन्हीं आधारों पर बड़ी संख्या में लोगों के राशन कार्ड काटने के संदेश भी भेजे गये हैं। इन्हीं संदेशों के आधार पर लोग अपनी दिहाड़ियां तोड़-तोड़ कर लाइनों में लगे खड़े हैं। जाहिर है कि लाइनों में लगे लोगों के पास अन्य कुछ सोचने व करने का समय ही नहीं बच पायेगा।

खट्टर सरकार ने पेंशन काटने का एक नया फार्मूला और ईजाद किया है जिसके अनुसार पांच यूनिट से अधिक बिजली जलाने वाला परिवार गरीब नहीं माना जायेगा। यानी जो परिवार महीने में 150 यूनिट से अधिक बिजली का उपभोग करता है उसे गरीबों को मिलने वाली कोई भी सहायता के काबिल नहीं समझा जायेगा। इसी को आधार बना कर खट्टर सरकार बड़े पैमाने पर गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा कर उन्हें मिलने वाली सुविधाओं से वंचित कर रही है।

परिवार पहचान पत्र के चक्रव्यूह को समझने के लिये करनाल का एक उदाहरण प्रस्तुत है। वहां रहने वाले हरियाणा पुलिस के एक सेवानिवृत डीजीपी को किसी काम के लिये इस पहचानपत्र की जरूरत पड़ी तो उन्होंने वहां के उपायुक्त को फ़ोन किया। उपायुक्त ने तुरन्त अपने एक बाबू को उनके पास सम्बन्धित कागजात लेकर यह काम करवाने के लिये भेजा। दफ्तरी कामों से हर रोज़ निपटने वाले उस बाबू को भी डीजी साहब के घर और अपने दफ्तर के तीन चक्कर काटने पड़े तब जाकर कहीं एक सप्ताह में यह पहचान पत्र बन पाया। समझना कठिन नहीं है इस काम के लिये एक आम आदमी के साथ क्या-क्या बीतती होगी? दरअसल इसका उद्देश्य ही जनता की चक्रघिन्नी बनाये रखना है, जिसमें खट्टर सरकार कामयाब नजर आ रही है।

# अधिकारियों की लापरवाही से 6 लेन सड़क का काम अधर में लटका

**फरीदाबाद।** सेक्टर 55 के ठीक सामने 30 मीटर 100 फुट रोड इस सड़क को सेक्टर 24 के सोहना मोड से लेकर समयपुर चुंगी तक सिक्स लेन बनाया जाना था। जिसका काम आर.के गांधी कंस्ट्रक्शंस कंपनी को एचएसवीपी विभाग द्वारा दिए हुए लगभग एक साल होने जा रहा है। लेकिन केवल 30 प्रतिशत निर्माण कार्य 6 महीने पहले शुरू होने के 15 दिन बाद ही बंद कर दिया गया। जबकि अधिकारियों को कार्य शुरू होने से पहले ही बिजली के पोल हटवा देने चाहिए थे। यह पोल भी एचएसवीपी इलेक्ट्रिकल विभाग के कार्यकारी अभियंता अश्वनी गॉड द्वारा ही हटवाए जाने थे। एक ही विभाग होने के बावजूद एचएसवीपी अधिकारियों ने जानबूझकर सड़क को जगह-जगह से खोदकर खुला छोड़ दिया है। आए दिन वहां से गुजरने वाले सभी पैदल, साइकिल सवार, टू व्हीलर या अन्य वाहन चालक आदि परेशानियों का सामना करते हुए विभाग और सरकार दोनों को कोसते रहते हैं।

अधिकारियों की लापरवाही से सरकार की बदनामी हो रही है। कभी भी कोई बड़ा हादसा होने के बाद ही शायद शासन व प्रशासन की आंखें खुलेगी। इतना सब भी तब हुआ जब जहां स्थानीय लोगों ने 10 दिन तक धरना प्रदर्शन इस सड़क के निर्माण के लिए किया था। उसके बाद ही स्वयं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और अन्य जनप्रतिनिधियों ने मौके पर पहुंचकर लगभग 1 दर्जन से अधिक नारियल फोड़कर अपने-अपने फोटो भी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजे थे। लेकिन अब इस समस्या की सुध लेने वाला कोई दूर तक भी नजर नहीं आ रहा है। जल्द ही बकाया सड़क का निर्माण शुरू नहीं किया गया तो आने वाले धुंध और कोहरे के मौसम में कोई भी बड़ा हादसा होने की पूरी संभावना है। इस समस्या और सड़क की हालत को देखकर स्थानीय लोगों में अंदर ही अंदर रोष धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उस हालात के बाद स्थानीय लोग यदि कोई कठोर कदम उठाएंगे तो, उसकी पूरी जिम्मेवारी व जवाबदारी स्थानीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पर होगी।

यह कार्य ठेकेदार की मृत्यु के एक महीने बाद शुरू हुआ था और शुरू करने के 15 दिन बाद ही खंबे सड़क के बीचो बीच होने के कारण काम बंद करना पड़ा इलेक्ट्रिकल डिवीजन एचएसवीपी द्वारा खंबे हटाए जाने के विषय में जानबूझकर लापरवाही और देरी बरती गई है सिविल डिपार्टमेंट को उन्हें पहले ही सूचित करना चाहिए था इसके लिए सिविल विभाग एचएसवीपी डिवीजन-1 भी बराबर का दोषी है